



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

निर्णय सुरक्षित रखने की दिनांक	निर्णय पारित किया जाने कि दिनांक	वह तिथि जब निर्णय वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है	
		ऑपरेटिव	फूल
23-09-2025	28-11-2025	-----	25.11.2025

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित किया गया : 23-09-2025

निर्णय पारित किया गया: 28-11-2025

दाण्डिक अपील सं 1282/2018

रामावतार पिता रामकुमार उरांव ,29 वर्ष, निवासी गाँव पाखरीखर सूर, पुलिस थाना सीतापुर, जिला सरगुजा
छत्तीसगढ़

---अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस थाना सीतापुर के द्वारा, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु : --श्री राकेश कुमार झा तथा श्री विवेक सिद्धार्थ ओझा, अधिवक्ता।

उत्तरवादी हेतु : --श्री अंकुर कश्यप, उप शासकीय अधिवक्ता।

माननीय श्रीमती रजनी दुबे, न्यायाधीश



तथा

श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

सीएवी निर्णय

रजनी दुबे, न्यायाधीश के अनुसार,

इस अपील में माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफटीसी, सरगुजा (अंबिकापुर) द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2018 को एसटी संख्या 393/2011 में पारित दोषसिद्धि और दंड के आदेश की वैधता और औचित्य को चुनौती दी गई है, जिसके तहत आरोपी/अपीलकर्ता को निम्नलिखित रूप से दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है:

दोषसिद्धि	दंड
भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत।	5 वर्ष का कठोर कारावास, 500 रुपये का जुर्माना और जुर्माना न भरने पर एक महीने का साधारण कारावास।
भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत।	10 वर्ष के कठोर कारावास, 500 रुपये का जुर्माना और जुर्माना न भरने पर एक महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1) के तहत।	आजीवन कारावास, 500 रुपये का जुर्माना और जुर्माना न भरने पर एक महीने का साधारण कारावास।
भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत।	आजीवन कारावास, 500 रुपये का जुर्माना और जुर्माना न भरने पर एक महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।

सभी दंड को साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

02. अभियोजन पक्ष का प्रकरण, संक्षेप में, यह है कि 27.05.2011 को मृतक अपने नाना-नानी के गांव के रूपेश उरांव के विवाह समारोह में बस से चैनपुर गांव गई थी। उसके साथ अन्य ग्रामीण भी थे, जिनमें आरोपी/अपीलकर्ता भी शामिल था। उसके पिता (पीडब्लू-1) भी चैनपुर गांव में अपनी सास (पीडब्लू-2) और ससुर (पीडब्लू-3) के घर गए थे, जहां मृतक भी मौजूद थी। पूछे जाने पर मृतक ने बताया कि वह आरोपी के साथ आई थी। विवाह समारोह समाप्त होने के बाद, जब उसके पिता उसे वापस गांव ले जाने के लिए अपने ससुर के घर गए, तो वह वहां नहीं मिली। उसकी सास पीडब्लू-2 ने बताया कि रात लगभग 8-9 बजे मृतक आरोपी के साथ आई थी और कह रही थी कि वह उसके साथ बस से वापस आ जाएगी। उसके पिता ने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। लगभग रात 1 बजे जब बारात गांव लौटी, तो उसकी मुलाकात आरोपी से हुई और उसने अपनी पुत्री के बारे में पूछा, जिस पर उसने बताया कि उसने उसे उसकी नानी के घर छोड़ दिया था। हालांकि, अगले दिन जब वह अपने भतीजे सुशील के साथ चैनपुर गांव गए, तो गांव के कोटवार ने उन्हें



सूचना दी कि खेत में एक लड़की मृत पड़ी है। वे वहां गए और देखा कि वह उनकी बेटी है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

03. अन्वेषण के दौरान, पुलिस ने 28.5.2011 को मामला संख्या 53/2011 (एक्स पी/1) दर्ज किया, घटनास्थल का नक्शा (एक्स पी/6) और जांच ज्ञापन (एक्स पी/5) तैयार किया, घटनास्थल से प्लास्टिक की चप्पलें और एक अंडरवियर जब्त किया और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां डॉ. विद्याभूषण टोप्पो (पीडब्लू-8) ने पोस्टमार्टम किया और रिपोर्ट (एक्स पी/10) दी। आरोपी के पिता द्वारा पेश किए जाने पर उसके वस्त्र भी जब्त कर लिए गए। जब्त किए गए सामान को एफएसएल (कानूनी मानक सेवा) में रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद, आरोपी का डीएनए परीक्षण भी किया गया था। सामान्य अन्वेषण पूरी होने पश्चात् आरोपी/अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 376(2)(एफ) और 302 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। माननीय विचारण न्यायालय ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376(1) और 302 के तहत आरोप निर्धारित किए, जिस पर उसने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और विचारण की मांग की।

04. अपने प्रकरण को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 13 साक्षियों से परीक्षा की। आरोपी का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के प्रकरण में उसके खिलाफ लगे सभी दोष सिद्ध करने वाले तथ्यों से इनकार किया, अपनी निर्दोषता का दावा किया और झूठे फँसाए जाने की बात कही। हालाँकि, अपने बचाव में उनके द्वारा किसी भी साक्षी से पूछताछ नहीं परीक्षा ।

05. संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं की सुनवाई और अभिलेख में मौजूद मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को उपरोक्त अनुसार दोषी ठहराया तथा दंड पारित किया गया। अतः यह अपील प्रस्तुत किया गया है।

06. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं आक्षेपित निर्णय स्वतः ही अवैध है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत है। अभियोजन पक्ष का पूरा प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, लेकिन ऐसी कोई पूर्ण घटनाक्रम नहीं है जो अपीलकर्ता के अपराध को संदेह से परे साबित करती है। पीडब्लू-1 तथा पीडब्लू-2 के साक्ष्य के अनुसार, अपीलकर्ता और मृतक पीडब्लू-2 के घर से अलग-अलग निकले और उसके बाद उन्हें किसी ने भी साथ नहीं देखा। पीडब्लू-13 सीएस नेताम, अन्वेषण अधिकारी, ने बताया कि दो विलय की सूचनाएं थीं, अर्थात् विलय संख्या 51/2011 और विलय संख्या 53/2011, और अपीलकर्ता पर विलय संख्या 51/2011 के संबंध में वाद चलाया गया है। इससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न होता है। इस प्रकरण में मृतक का शव जिस स्थान पर मिला था, वह भी विवादित है। उनका कहना है कि अपीलकर्ता की डीएनए जांच रिपोर्ट भी संदिग्ध है क्योंकि उसके रक्त के नमूने को ठीक



से संरक्षित नहीं किया गया था और आरोपी के रक्त के नमूने एकत्र करने और डीएनए परीक्षण के लिए भेजने की दिनांक में गंभीर विसंगतियां हैं। अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता को इस अपराध को अंजाम देने का कोई मकसद साबित करने में भी विफल रहा है। इस प्रकार, साक्ष्य की प्रकृति और गुणवत्ता को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध अपने प्रकरण को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और इसलिए, अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से दोषमुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 12 मई, 2016 के निर्णय (सीआरए संख्या 462/2016) पर भरोसा किया गया है, जिसमें रामब्रक्ष @ जालिम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य का निर्णय शामिल है; राजा नायकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में 24 जनवरी, 2024 को सीआरए संख्या 902/2023 में दिया गया फैसला; चोटकाऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) 6 एससीसी 742 में प्रकाशित निर्णय; करक्कट्टू मोहम्मद बशीर बनाम केरल राज्य के मामले में 5 नवंबर, 2024 को सीआरए संख्या 291/2023 में दिया गया फैसला; और कट्टवेलाई @ देववाकर बनाम तमिलनाडु राज्य (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1439 में प्रकाशित फैसला शामिल हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 24 फरवरी, 2025 का निर्णय, सीआरए संख्या 1649/2011 में मोहम्मद बानी आलम मजीद उर्फ धन बनाम असम राज्य के मामले में; इस न्यायालय का 22.2.2023 का निर्णय, सीआरए संख्या 565/2022 में किशन लाल उर्फ चंपा यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में और इस न्यायालय का 13.11.2024 का निर्णय, सीआरए संख्या 1484/2019 में धनेश्वर उर्फ टेडू उर्फ रोन्हा पांदो बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में।

07. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता के तर्क का विरोध करते हुए कहा कि अभिलेख में मौजूद मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर, निचली अदालत ने अपीलकर्ता को उचित रूप से दोषी ठहराया है और सजा सुनाई है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

08. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

09. विचारण न्यायालय के अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 363, 366, 376(1) और 302 के तहत आरोप लगाया गया था और मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद, विचारण न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया और इस निर्णय के कंडिका 1 में उल्लिखित दंड पारित किया गया।

10. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाने वाला पहला प्रश्न यह है कि क्या मृतक की मृत्यु हत्या थी और क्या उसकी मृत्यु से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था?



11. मृतक के पिता, पीडब्लू-1 ने बताया कि मृतक उनकी बेटी थी और उसकी उम्र लगभग 8-9 वर्ष थी। वह चैनपुर गांव में एक विवाह समारोह में गए थे, जहां उनके ससुराल का घर स्थित है। वहां उन्होंने अपनी पुत्री को बैठे देखा और आरोपी भी वहीं मौजूद था। उन्होंने आरोपी को अपने साथ ससुराल चलने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं आया, इसलिए वह अपने भतीजे के साथ विवाह के घर चले गए। हालांकि, शाम लगभग 7 बजे जब वह अपने भतीजे के साथ ससुराल लौटे, तो मृतक और आरोपी वहां नहीं थे। पूछे जाने पर, उनकी सास ने बताया कि मृतक ने यह कहकर घर छोड़ दिया कि वह आरोपी के साथ बस से जा रही है। इसके बाद उसने उसकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अगले दिन जब वह अपने भतीजे सुशील कुमार के साथ मृतक की तलाश में चैनपुर गांव में अपने ससुराल वापस गया, तो वहां चौकीदार ने उसे बताया कि खेत में उसकी हत्या कर दी गई है। इसके बाद, वे बताए गए स्थान पर गए और वहाँ उसका शव पड़ा हुआ पाया। उन्होंने विलय की सूचना (एक्स पी/1) दर्ज कराई, जिस पर उनके हस्ताक्षर ए से ए तक हैं।

12 पीडब्लू-5 जगमोहन ने नोटिस (एक्स पी/4) और जांच ज्ञापन (एक्स पी/5) पर ए से ए तक अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। पीडब्लू-13 सीएस नेताम, अन्वेषण अधिकारी, ने बताया कि उन्होंने साक्षियों के समक्ष विलय की सूचना (एक्स पी/1) दर्ज कराई, जांच के लिए नोटिस (एक्स पी/4) जारी किया और जांच ज्ञापन (एक्स पी/5) तैयार किया, साथ ही पोस्टमार्टम के लिए आवेदन (एक्स पी/9 ए) भी दिया।

13. पीडब्लू 8 डॉ. विद्याभूषण टोप्पो ने डॉ. एम. निकुंज के साथ मृतक का पोस्टमार्टम किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:

“बाह्य परीक्षण: अकड़न मौजूद है। नाखून के नीचे का भाग नीला पड़ गया है। बाईं आंख में चोट लगी है और कंजंक्टिवा में रक्त प्रवाह रुका हुआ है। जीभ बाहर निकली हुई है और ऊपर और नीचे दोनों दांतों के बीच दबी हुई है। नाक से खून बह रहा है। दाहिने गाल और माथे पर खरोंचें हैं। चेहरा सूजा हुआ है, दाहिना हाथ सूजा हुआ है (बांह) और दाहिनी और बाईं बांह, गर्दन और छाती में शिराओं में रक्त का प्रवाह रुका हुआ है। निप्पल के भीतरी भाग में दाहिने स्तन पर नाखून जैसे निशान मौजूद हैं। योनि के आसपास से रक्तस्राव हो रहा है। पीठ के पिछले भाग के दाहिने हिस्से पर खरोंच है। साथ ही दोनों कोहनियों के क्षेत्र में भी खरोंच है। गुदा से मल त्याग हुआ है। गर्दन में सूजन है। हाइमन फटा हुआ है और लेबिया मैनोरा में खरोंच है।

आंतरिक परीक्षण: श्वास नलिका फटी हुई है। हाइमन का फटना यौन संबंध के कारण हो सकता है।” उनके अनुसार, मृत्यु का कारण गला घोटने से हुई घुटन थी तथा मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी। उन्होंने पांच योनि स्लाइड भी तैयार कीं और मृतक के गुप्तांग और सिर के बालों के नमूनों के साथ-साथ उसके वस्त्रों को भी सीलबंद करके रासायनिक परीक्षण के लिए कांस्टेबल को सौंप दिया। प्रतिपरीक्षा में, पीडब्लू 8 ने स्वीकार किया कि उसने केवल योनि के फटने के बारे में लिखा था और यह उल्लेख नहीं किया था कि यह पुराना फटना था या नया। उसने स्पष्ट किया कि चूंकि रक्तस्राव हो रहा था, इसलिए फटना नया था। वह यह भी कहता है कि



पोस्टमार्टम के दौरान उसके शरीर पर पाए गए घावों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु के समय उसने संघर्ष किया था।

14. एफएसएल रिपोर्ट (एक्स पी/ 21) में मृतक के आर्टिकल एफ - योनि स्लाइड, मृतक के जी-1 फ्रॉक, आरोपी के एच-1 और एच-2 अंडरवियर और पैंट पर मानव शुक्राणु पाए गए थे। प्रतिपरीक्षा में बचाव पक्ष साक्षियों से ऐसा कुछ भी नहीं निकलवा सका जिससे उपरोक्त चिकित्सा और फोरेंसिक साक्ष्य संदिग्ध साबित हो सकें। इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने इस तथ्य को संदेह से परे साबित कर दिया है कि मृतक की मृत्यु हत्या थी और उसकी मृत्यु से पहले उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए गए थे।

15. अब हमें विचार करना होगा कि क्या यह अभियुक्त/अपीलार्थी है जो इस अपराध का लेखक है?

16. विद्वत विचारण न्यायालय ने समग्र साक्ष्य की सराहना करने के पश्चात् पाया कि अपीलार्थी के विरुद्ध कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं जो अपने अपराध को पूरी तरह से साबित करते हैं तथा आक्षेपित निर्णय के कंडिका 65 में इसे निम्नानुसार चित्रित किया है:

"65 इस प्रकरण की परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियों एक-दूसरे से ऋखलाबद्ध तरीके से सशक्त रूप से जुड़ी हुई प्रमाणित हुई है। जिसके आधार पर और कोई नहीं अपितु अभियुक्त रामअवतार के द्वारा ही उक्त अपराध किया जाना पूर्ण रूप से निम्न आधारों से प्रमाणित होता है-

1. घटना दिनांक 27-28/05/2011 को मृतिका का अभियुक्त के साथ ग्राम पकरीखार से ग्राम चैनपुर बारात में बस से जाना।

2. ग्राम चैनपुर पहुँचने के बाद मृतिका को उसके नानी-नाना के घर अभियुक्त के साथ में पाया जाना।

3. मृतिका का ग्राम चैनपुर के शादी घर से वापस ग्राम पकरीखार न आना।

4. अभियुक्त का ग्राम चैनपुर से ग्राम पकरीखार बारात के साथ अकेले वापस आना, किंतु मृतिका के बारे में कुछ नहीं बताना, मृतिका के पिता के पूछने पर ग्राम चैनपुर में मृतिका को उसके नाना नानी के यहाँ छोड़ देना एवं सायकल से भागने का प्रयास करना।

5. पश्चातवर्ती कम में मृतिका के शव का ग्राम चैनपुर स्थित घटनास्थल में पाया जाना।

6. अभियुक्त के द्वारा घटना के समय पहने गये जप्तशुदा खाकी रंग के फुलपैट में रक्त के पाये जाने का अभियुक्त द्वारा कोई समाधानपरक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना।

7. डी.एन.ए. परीक्षण रिपोर्ट में उक्त जप्तशुदा फुलपैट में पाया गया रक्त अभियुक्त का होना।"

17. मृतक के पिता, पीडब्लू-1 ने बताया कि उन्होंने आरोपी और मृतक को अपने ससुराल में बैठे देखा था और जब वे मायके से लौटे तो उन्हें दोनों ससुराल में नहीं मिले। उन्होंने बताया कि उनकी सास ने उन्हें बताया कि



मृतक यह कहकर चली गई कि वह आरोपी के साथ बस से जा रही है। उन्होंने मृतक की तलाश की लेकिन वह नहीं मिली। जब उन्होंने आरोपी से अपनी पुत्री के बारे में पूछा तो वह चुप रहा। अगले दिन जब उन्होंने फिर से आरोपी से अपनी पुत्री के बारे में पूछा और उसे अपनी पुत्री की तलाश के लिए चैनपुर गांव चलने को कहा, तो वह (आरोपी) भागने लगा।

18. मृतक की नानी (पीडब्लू-2) ने बताया कि मृतक आरोपी के साथ विवाह में शामिल होने के लिए चैनपुर गांव आई थी। जब उन्होंने मृतक से पूछा कि वह किसके साथ आई है, तो आरोपी ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि वह उसे यहां लाया है और अपने साथ वापस ले जाएगा। कुछ समय बाद, मृतक आरोपी के साथ मायके चली गई। प्रतिपरीक्षा में उन्होंने स्वीकार किया कि आरोपी और मृतक दोपहर में उनके घर आए थे और 1-2 घंटे बाद वे मायके चले गए। कंडिका 4 में उन्होंने बताया कि जब उन्होंने मृतक से पूछा कि वह अपने माता-पिता के साथ क्यों नहीं आई, तो उसने जवाब दिया कि वह बारात में अकेली आई है। उन्होंने स्वीकार किया कि मृतक घर में किसी को भी बिना बताए विवाह में आई थी और उन्होंने उसे बिना बताए आने के लिए डांटा भी था। वह कहती है कि घटना से पहले वह आरोपी को नाम से भी नहीं जानती थी और ग्रामीणों के कहने पर ही उसे रामावतार के रूप में पहचान रही है।

19. मृतक के नाना (पीडब्लू-3) बताते हैं कि मृतक आरोपी के साथ उनके घर आई थी और जब उन्होंने उससे आने का कारण पूछा, तो उसने कहा कि वह आरोपी के साथ आई है। उस समय, आरोपी ने उनसे कहा कि वह उनके साथ आई है और वह उसे वापस छोड़ देंगे। इसके बाद, उसने उनके घर में भोजन किया और चली गई और कुछ समय बाद आरोपी भी उनके घर से चला गया। वह बताते हैं कि लगभग रात 8 बजे वह यह पता लगाने के लिए मायके घर गए कि मृतक वापस गई है या नहीं, उन्हें मृतक और आरोपी वहां नहीं मिले, इसलिए वह अपने घर लौट आए और सो गए क्योंकि आरोपी ने कहा था कि वह उसे अपने घर छोड़ देगा।

20. मृतक के नाना (पीडब्लू-3) के बयान से यह स्पष्ट है कि मृतक पहले उनके घर से निकली और कुछ समय बाद आरोपी भी उनके घर से निकला। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए किसी भी साक्षी ने उन दोनों को एक साथ बस से मायके जाते हुए या पीडब्लू-3 के मायके के लिए एक साथ निकलते हुए नहीं देखा। इस प्रकार, यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक को जीवित रहते हुए आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था।

21. पीडब्लू 13, सीएस नेताम, जांच अधिकारी, ने 29.5.2011 को आरोपी की पैंट जब्त की (जबती ज्ञापन एक्स पी/ 15 के अनुसार) और 2.6.2011 को आरोपी का एक अंडरवियर जब्त किया (जबती ज्ञापन एक्स पी/ 16 के अनुसार)। उन्होंने आरोपी के गुवांग की जांच और उस पर लगे स्मेग्मा को सुरक्षित रखने के लिए एक ज्ञापन भी लिखा (एक्स पी/ 3 के अनुसार)। 23.6.2011 को उन्होंने जेएमएफसी, सीतापुर को डीएनए परीक्षण के लिए आरोपी के रक्त का नमूना लेने की अनुमति हेतु आवेदन दिया (एक्स पी/ 23 के अनुसार)। उन्होंने बताया कि उन्होंने डीएनए परीक्षण के लिए आरोपी से रक्त का नमूना लेने की सहमति प्राप्त



कर ली थी (एक्स पी/ 24 के अनुसार) और सीडीएफडी, हैदराबाद से डीएनए रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद (एक्स पी/ 25 के अनुसार) उन्होंने इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

22. डीएनए रिपोर्ट के अनुसार, डीएनए परीक्षण के लिए निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुईं:

स्रोत का नाम	प्राप्त/संग्रहित	प्रदर्शनी
योनि स्वैब स्लाइड मृतक की बताई गई है।	29-08-2011	ए
अंडरवियर श्री रामावतार (आरोपी) का बताया गया	29-08-2011	बी
प्लांट को श्री रामावतार (आरोपी) का बताया गया है	29-08-2011	सी
योनि से एकत्र किया गया एक बाल का टुकड़ा	29-08-2011	डी
मृतक के सिर से बालों का गुच्छ एकत्र किया गया था	29-08-2011	ई
श्री रामावतार का बताया जा रहा खून से सना हुआ एफटीए कार्ड, पहचान पत्र संख्या 1	29-08-2011	एफ

सरगुजा के पुलिस अधीक्षक ने जब्त की गई वस्तुओं के डीएनए परीक्षण के लिए रायपुर स्थित एफएसएल निदेशक को आवेदन पत्र (एक्स पी/ 20) भेजा। इस पत्र पर केवल सरगुजा के पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर हैं, और इस पर 7.8.2011 की दिनांक अंकित है। इस पत्र में कांस्टेबल का नाम भी नहीं लिखा है। सरगुजा के पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखे गए एक अन्य ज्ञापन में भी तारीख नहीं है, लेकिन उस पर कांस्टेबल प्रवीण का नाम (खालखो संख्या 216) लिखा है। फिर 23.8.2011 को एसपी, सरगुजा ने निदेशक, सीडीएफडी, हैदराबाद को संलग्न प्रदर्शनों की सूची में उल्लिखित कुछ वस्तुओं की डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए एक पत्र लिखा, जो इस प्रकार है:

सरल क्रमांक	प्रदर्शनियों के नाम	किसे कहाँ और	प्रदर्शनी का स्रोत	टिप्पणी करें
-------------	---------------------	--------------	--------------------	--------------



		कब जब्त किया गया		
1)	वी. एस. स्लाइड (3 संख्या)	दिनांक 4.6.11 को पीएम के दौरान ऑटोप्सी सर्जन द्वारा	मृतक।	"एफ "
2)	कपड़े (एक जांगिया तथा एक पैंट)	आई. ओ. इंस्पेक्टर सी. एस. नेताम द्वारा दिनांक 2.6.11 और 29.5.11 पर अभियुक्त से	अभियुक्त रामावतार	"एच "
3)	मृतक की योनि में प्यूबिक बाल पाए गए जबकि उसके कोई प्यूबिक बाल नहीं हैं	दिनांक 4.6.11 को पीएम के दौरान ऑटोप्सी सर्जन द्वारा	मृतक।	"आई "
4	खून का नमूना	सहायक सर्जन द्वारा (ब्लड बैंक प्रभारी) दिनांक 24.6.11 को।	अभियुक्त रामावतार	"जे "

23. पीडब्लू- 13, सीएस नेताम ने 23.06.2011 को डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए आरोपी की सहमति प्राप्त की (प्रदर्श पृष्ठ 23 और 24 देखें)। पीडब्लू- 7, डॉ. आज्ञाद भगत ने बताया कि 24.06.2011 को उन्होंने डीएनए परीक्षण के लिए आरोपी का रक्त नमूना एकत्र किया और उसकी तस्वीर भी ली गई। रक्त नमूने को सील करके फोरेंसिक प्रयोगशाला को भेजा गया (प्रदर्श पृष्ठ 8 देखें)। प्रदर्शित वस्तुओं की सूची में (प्रदर्श पृष्ठ 22 देखें) के अनुसार, आरोपी का रक्त नमूना, यानी वस्तु "जे", 24.06.2011 को प्राप्त किया गया था, जबकि डीएनए रिपोर्ट (प्रदर्श पृष्ठ 25 देखें) में, वस्तु एफ, यानी रक्त से सना हुआ एफटीए कार्ड, जो आरोपी का बताया जा रहा है और मृतक के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाता है, 29.08.2011 को प्राप्त/एकत्रित किया गया था। अन्वेषण अधिकारी सी. एस. नेताम ने कंडिका 17 में कहा है:

"17- प्रदर्श पी-20 पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से तैयार किया गया है इसलिये मैं नहीं बता सकता कि उसे किसने तैयार किया है और किस तारीख तैयार किया है, साक्षी स्वतः कहा कि हस्ताक्षर के नीचे दिनांक



अंकित है जो अस्पष्ट है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-20 के शीर्ष पर दिनांक का स्थान रिक्त है। यह बात सही है कि एस.पी. की अनुपस्थिति में एडिशन एस.पी. ही एस.पी. का कार्य देखते हैं। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-20 में जब्त वस्तुओं को रासायनिक जांच हेतु ले जाने वाले आरक्षक का नाम उल्लेखित नहीं है, वह स्थान रिक्त है। मैं आज यह नहीं बता सकता कि रासायनिक परीक्षण हेतु किस दिनांक को जब्त वस्तुओं को रायपुर भेजा गया था। यह बात सही है कि डी.एन.ए. टेस्ट हेतु सी.डी.एफ.डी. हैदराबाद को जब्तशुदा वस्तु कब प्राप्त हुआ इसकी पावती इस अभियोग पत्र के साथ संलग्न नहीं है। यह बात भी सही है कि सी.डी.एफ.डी. हैदराबाद से अपराध क्रमांक 148/2011 से संबंधित जांच रिपोर्ट कौन लेकर थाना में प्रस्तुत किया यह मैं नहीं बता पाऊंगा। यह कहना गलत है कि आरोपी रामअवतार से जो डी.एन.ए. टेस्ट हेतु ब्लड सैंपल लेना बताया हूँ वह सैंपल डी.एन.ए. टेस्ट हेतु नहीं भेजा था। यह कहना गलत है कि मैं अंजन नामक व्यक्ति को बचाने के लिये आरोपी रामअवतार के वास्तविक ब्लड सैंपल को जांच के लिये नहीं भेजा था बल्कि अंजन का ब्लड मैं तथा अधिकारियों से मिलकर रामअवतार को फंसाने के लिये झूठा रिपोर्ट मनगढ़न्ती तौर से तैयार करवाकर इस प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत करवाया हूँ।"....

24. इस न्यायालय ने धनेश्वर उर्फ टेडू उर्फ रोन्हा पांडो (उपरोक्त) के प्रकरण में अपने निर्णय के कंडिका 18 और 19 में निम्नलिखित कहा:

"18. यदि अभियोजन पक्ष के इस प्रकरण को जैसा है वैसा ही मान लिया जाए कि अपीलकर्ता और मृतक को आखिरी बार 4.8.2012 की रात 8 बजे एक साथ देखा गया था, तो मृतक का शव अगली सुबह 5.8.2012 को 7-8 बजे के बीच खेमनिदी नामक व्यक्ति ने देखा, जिसने पीडब्लू-7 भुवनेश्वर को इसकी सूचना दी। इस प्रकार, मृतक को अपीलकर्ता के साथ अंतिम बार देखे जाने और उसके शव की बरामदगी के बीच लगभग 12 घंटे का अंतर है। इस संबंध में, नवनीतकृष्णन बनाम राज्य बनाम पुलिस निरीक्षक (2018) 16 एससीसी 161 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्यपि अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्ष्य आरोपी के अपराध की ओर इशारा कर सकता है, लेकिन यह साक्ष्य अकेले ही आरोपी के अपराध को संदेह से परे साबित करने का भार वहन नहीं कर सकता है और इसके लिए पुष्टि की आवश्यकता है, और कंडिका 22 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है: --

"22. अ.सा. 11 न्यायालय में ही तीनों आरोपियों की पहचान करने में सक्षम था। उसने अपनी याददाश्त के आधार पर बताया कि वे वही लोग थे जो उस समय आए थे जब वह जॉन बॉस्को के साथ अपनी कार धो रहा था। उसने यह भी बताया कि उसने उन सभी को उस दिन ओमनी वैन में बैठे हुए देखा था। इस संबंध में उसका बयान जिरह के दौरान भी बरकरार रहा, क्योंकि उक्त गवाह की अपीलकर्ताओं के प्रति कोई शत्रुता नहीं है और वह एक स्वतंत्र साक्षी है। एक बार जब अ.सा. 11 का बयान साबित हो जाता है और उस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है, तो यह सुस्थापित हो जाता है कि मृतक के साथ आखिरी बार आरोपियों को ही देखा गया था, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जब अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि वे आरोपियों से अलग हुए थे और तब से मृतक की कोई गतिविधि का पता नहीं लगाया जा सका है और



उनके शव बाद में बरामद किए गए थे। यह एक स्थापित विधिक स्थिति है कि विधि यह उपधारणा करता है कि मृतक के साथ आखिरी बार देखे गए व्यक्ति ने ही मृतक की हत्या की होगी और इस धारणा का खंडन करने का भार आरोपी पर होता है कि वह व्यक्ति वहां से चला गया था। निस्संदेह, अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत उन परिस्थितियों की कड़ी में एक महत्वपूर्ण घटना है जो आरोपी के अपराध को पूरी तरह से साबित कर सकती है और/या कुछ हद तक निश्चित रूप से उसकी ओर इशारा कर सकती है। हालांकि, केवल यही साक्ष्य आरोपी के अपराध को संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसके लिए पुष्टि की आवश्यकता है।

19. वर्तमान प्रकरण में, पुष्टि के रूप में इस तथ्य के अलावा कुछ भी दर्ज नहीं किया गया है कि घटना स्थल से खून से सना चाकू बरामद किया गया था, हालांकि एफएसएल रिपोर्ट में उक्त चाकू पर खून नहीं पाया गया था। इस संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने बोबी बनाम केरल राज्य (2023 लाइव लॉ (एससी) 50) मामले में, चंद्रन बनाम तमिलनाडु राज्य (1978) 4 एससीसी 90 और कर्नाटक राज्य बनाम डेविड रोजारियो और अन्य (2002) 7 एससीसी 728 मामलों में दिए गए निर्णयों का अनुसरण करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि आरोपी का कोई संस्वीकृति कथन नहीं है जिससे सामग्री की बरामदगी हो सके, तो शव की बरामदगी को आरोपी के कहने पर हुई बरामदगी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार, घटना स्थल से चाकू की बरामदगी अभियोजन पक्ष के लिए किसी काम की नहीं है। इसी प्रकार, घटनास्थल से बरामद चप्पलों को भी अपीलकर्ता की चप्पलें साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभियोजन पक्ष का यह दावा नहीं है कि घटनास्थल से जब्त की गई चप्पलें इतनी विशेष गुणवत्ता की थीं कि वे स्थानीय बाजार में उपलब्ध न हों। इसके अलावा, जब्त की गई चप्पलों की पहचान नहीं की गई जिससे यह साबित हो सके कि वे वास्तव में अपीलकर्ता की थीं और अपीलकर्ता ने घटना के समय उन्हें पहना था।"

25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टेवैल्लई @ देवकर (उपरोक्त) मामले में अपने निर्णय के कंडिका 44 में डीएनए साक्ष्य से जुड़े मामलों में पालन किए जाने वाले कुछ निर्देश जारी किए, जो इस प्रकार हैं:

"44. पालन की जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया का यह अभाव चिंताजनक है। इस प्रकार, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं जिनका पालन अब से डीएनए साक्ष्य से जुड़े सभी मामलों में किया जाएगा:

1. डीएनए नमूने एकत्र करने के बाद, उचित सावधानी बरतते हुए और सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, जिनमें त्वरित और उपयुक्त पैकेजिंग शामिल है, नमूने विधिवत रूप से दर्ज किए जाएंगे। इन नमूनों में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:

- क) एफआईआर संख्या और तिथि;
- ख) धारा और उससे संबंधित विधि;
- ग) अन्वेषण अधिकारी (पुलिस स्टेशन) का विवरण;
- और घ) आवश्यक क्रम संख्या।



संग्रह संबंधी दस्तावेज़ में उपस्थित चिकित्सा पेशेवर, जांच अधिकारी और स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर और पदनाम होने चाहिए। यहां हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि स्वतंत्र साक्षियों की अनुपस्थिति को साक्ष्य संग्रह में बाधक नहीं माना जाएगा, लेकिन ऐसे साक्षियों को शामिल करने के प्रयास और अंततः ऐसा करने में असमर्थता को रिकॉर्ड में विधिवत रूप से दर्ज किया जाएगा।

2. डीएनए साक्ष्य को संबंधित पुलिस स्टेशन या अस्पताल तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी अन्वेषण अधिकारी की होगी। वह यह सुनिश्चित करने के लिए भी ज़िम्मेदार होगा कि लिए गए नमूने शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में नमूने लेने के 48 घंटों के भीतर संबंधित फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला तक पहुँच जाएँ। यदि कोई अप्रत्याशित परिस्थिति उत्पन्न होती है और 48 घंटों की समय सीमा का पालन नहीं किया जा सकता है, तो देरी का कारण मामले की डायरी में विधिवत दर्ज किया जाएगा। नमूनों की प्रकृति के अनुरूप, उन्हें संरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएँगे। 3. डीएनए नमूनों को मुकदमे, अपील आदि की सुनवाई लंबित रहने के दौरान सुरक्षित रखने हेतु, किसी भी पैकेज को विचारण न्यायालय की स्पष्ट अनुमति के बिना खोला, बदला या पुनः सील नहीं किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट को किसी योग्य और अनुभवी चिकित्सा पेशेवर के इस कथन के आधार पर अनुमति देनी होगी कि इससे साक्ष्य की पवित्रता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और कोर्ट को यह आश्वासन होना चाहिए कि अन्वेषण/विचारण के उचित और न्यायसंगत परिणाम के लिए ऐसा कदम आवश्यक है।

4. नमूने एकत्र करने से लेकर तार्किक निष्कर्ष तक, अर्थात् आरोपी की दोषसिद्धि या बरी होने तक, एक अभिरक्षा श्रृंखला रजिस्टर बनाए रखा जाएगा जिसमें साक्ष्य की प्रत्येक गतिविधि को प्रत्येक छोर पर प्रतिहस्ताक्षर के साथ दर्ज किया जाएगा और उसका कारण भी बताया जाएगा। यह अभिरक्षा श्रृंखला रजिस्टर अनिवार्य रूप से विचारण न्यायालय अभिलेख के के भाग के रूप में संलग्न किया जाएगा। इसे बनाए रखने में विफलता की स्थिति में, 1.0. ऐसी चूक का स्पष्टीकरण देने के लिए उत्तरदायी होगा। सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक, हिरासत रजिस्टर की श्रृंखला और ऊपर निर्देशित अन्य सभी दस्तावेजों के नमूना प्रपत्र तैयार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें सभी जिलों में आवश्यक निर्देशों के साथ भेजा जाए।"

26. करककट्टू मुहम्मद बशीर (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले पर विचार करते हुए अपने निर्णय के कंडिका 10 और 11 में निम्नलिखित टिप्पणी की:

"10. आगे बढ़ने से पहले, इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित और स्थापित सिद्धांतों का उल्लेख करना उचित होगा, जो उन मापदंडों को निर्धारित करेंगे जिनके भीतर अभियोजन पक्ष के मामले की, यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, तो अपीलकर्ता द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध की स्थापना के संबंध में जांच की जानी है। रामरेड्डी राजेश खन्ना रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006) 10 एससीसी 172 के मामले में, इस न्यायालय ने समय-समय पर पारित विभिन्न पूर्व निर्णयों का उल्लेख करते हुए, उन प्रमुख सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया है जो न्यायालयों को उन मामलों में आरोपी के अपराध के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं जो पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर निर्भर होते हैं।



इन्हें "पंचशील सिद्धांत" कहा गया है और उक्त निर्णय के कंडिका 26 से 28 में इनकी चर्चा की गई है, जो इस प्रकार हैं:

26. यह अब सर्वविदित है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि के लिए, अभियोजन पक्ष को सभी दोष सिद्ध करने वाली परिस्थितियों को विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्यों द्वारा स्थापित करना होगा और इस प्रकार सिद्ध परिस्थितियाँ घटनाओं की ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जिससे आरोपी के अपराध के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष न निकल सके। हालात किसी और परिकल्पना पर आधारित नहीं हो सकते हैं। यह भी सर्वविदित है कि संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, सबूत का विकल्प नहीं हो सकता और न्यायालयों को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर ही किसी आरोपी को दोषी ठहराने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। (देखें - अनिल कुमार सिंह बनाम राज्य बिहार [(2003) 9 एस. सी. सी. 67:2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1167 तथा रेड्डी संपत कुमार बनाम ए. पी. राज्य (2005) 7 एस. सी. सी. 603:2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1710]

27. इसके अलावा, अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत तब लागू होता है जब आरोपी और मृतक को आखिरी बार जीवित देखे जाने के समय और मृतक के मृत पाए जाने के समय के बीच का अंतर इतना कम होता है कि आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध का कर्ता होने की संभावना असंभव हो जाती है। ऐसे प्रकरण में भी न्यायालय को कुछ ठोस सबूत तलाशने चाहिए।

28. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश ((2005) 3 एससीसी 114:2005 एससीसी (क्रिमिनल) 642) मामले में इस न्यायालय ने टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 123, कंडिका 22)

"22. अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत तब लागू होता है जब आरोपी और मृतक को आखिरी बार जीवित देखे जाने और मृतक के मृत पाए जाने के बीच का समय अंतराल इतना कम हो कि आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध करने की संभावना नगण्य हो जाए। कुछ मामलों में, लंबे अंतराल और अन्य व्यक्तियों के बीच आने की संभावना होने पर, यह साबित करना मुश्किल होगा कि मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था। आरोपी और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखे जाने के किसी अन्य पुख्ता सबूत के अभाव में, ऐसे मामलों में दोषी ठहराने का निष्कर्ष निकालना जोखिम भरा होगा। इस प्रकरण में, अ.सा. 3 और 5 के साथ-साथ पी डब्लू 2 के साक्ष्य से भी पुख्ता सबूत मिलते हैं कि मृतक और आरोपी को एक साथ देखा गया था।

(देखें - बोधराज बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य [(2002) 8 एस. सी. सी. 45:2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 201])

11. इसके बाद, इस न्यायालय के बाद के निर्णयों में उपरोक्त सिद्धांतों को दोहराया गया है और वे आज तक लागू हैं। इस प्रकार, इन बुनियादी स्थापित सिद्धांतों को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि घटनाओं का क्रम इस प्रकार स्थापित होना चाहिए कि न्यायालय के पास एक ही निष्कर्ष पर पहुँचने के अलावा कोई



विकल्प न हो, अर्थात् आरोपी व्यक्ति का अपराध। यदि घटनाओं के क्रम में किसी भी स्तर पर जरा सा भी संदेह उत्पन्न होता है, तो उसका लाभ आरोपी को ही मिलना चाहिए। मात्र संदेह, चाहे वह कितना भी प्रबल क्यों न हो, प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता है। परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि उससे केवल एक ही निष्कर्ष निकले, अर्थात् आरोपी का अपराध सिद्ध हो। यहाँ तक कि दोषसिद्धि के मामले में भी, यदि अपील में साक्ष्यों की श्रृंखला पूर्ण न पाई जाए या न्यायालय आरोपी के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर पहुँच सके, तो आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए, जिससे स्पष्टतः उसकी बरी होने की संभावना रहती है। अर्थात्, जब कोई कड़ी गायब हो, तो दोष सिद्ध करने का निर्णय दर्ज नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व है कि वह ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करे जो किसी आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में उसकी दोषसिद्धि को निर्णायक रूप से और एकमात्र सत्य के रूप में स्थापित करे, और ऐसे साक्ष्य घटनाओं की एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला स्थापित करें जिससे आरोपी की निर्दोषता के निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे।"

27. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मामलों में दोषसिद्धि के लिए स्थापित विधिक सिद्धांतों को दोहराते हुए उपरोक्त न्यायिक निर्णयों के आलोक में, यदि हम पिछले अनुच्छेदों में चर्चा किए गए वर्तमान मामले के तथ्यों और साक्ष्यों की जांच करें, तो यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि अपीलकर्ता को मृतक के साथ उसके जीवित रहते हुए अंतिम बार देखा गया था और उनके अंतिम बार एक साथ देखे जाने और उसके शव के मिलने के समय के बीच का अंतराल इतना कम है कि यह अपीलकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध का कर्ता होने की संभावना को खारिज करता है। अभिलेख में उपलब्ध दूसरा परिस्थितिजन्य साक्ष्य डीएनए परीक्षण रिपोर्ट (एक्स पी/ 25) है, जिसके अनुसार मृतक का डीएनए प्रोफाइल आरोपी के रक्त के नमूने के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाता है। हालांकि, जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी का रक्त नमूना रासायनिक परीक्षण के लिए कब भेजा गया था। पीडब्लू-7 डॉ. आज़ाद भगत ने 24.6.2011 को आरोपी का रक्त नमूना एकत्र किया था और एसपी, सरगुजा (एक्स पी/20) के दिनांक 7.8.2011 के पत्र के अनुसार, एच एंड आई अर्थात् आरोपी के कपड़े डीएनए परीक्षण के लिए भेजे गए थे। डीएनए रिपोर्ट एक्स पी/ 25 में, आरोपी का बताया गया रक्त से सना हुआ एफटीए कार्ड 29.8.2011 को प्राप्त/एकत्रित किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार, आर्टिकल बी आरोपी का अंडरवियर है जिसे 29.8.2011 को जब्त किया गया था जबकि जब्ती ज्ञापन एक्स पी/16 से पता चलता है कि उसका अंडरवियर 2.6.2011 को जब्त किया गया था।

28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, जांच अधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि डीएनए नमूने उचित सावधानी और सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के अनुपालन के साथ एकत्र किए जाएं, जिसमें त्वरित और उचित पैकेजिंग भी शामिल है। अन्वेषण अधिकारी डीएनए साक्ष्य को संबंधित पुलिस स्टेशन या संबंधित अस्पताल तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होगा। वह यह सुनिश्चित करने के लिए भी



जिम्मेदार होगा कि इस प्रकार लिए गए नमूने शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में संग्रह के समय से 48 घंटों के भीतर संबंधित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला तक पहुंच जाएं। यदि कोई अप्रत्याशित परिस्थिति उत्पन्न होती है और 48 घंटों की समय सीमा का पालन नहीं किया जा सकता है, तो देरी का कारण केस डायरी में विधिवत दर्ज किया जाएगा वर्तमान प्रकरण में, यह स्पष्ट है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा 24.06.2011 को डीएनए परीक्षण के लिए आरोपी का रक्त नमूना लेने हेतु उसकी सहमति प्राप्त की गई (प्रदर्श पृष्ठ 24)। गवाह संख्या 7 डॉ. आज़ाद भगत के अनुसार, आरोपी का रक्त नमूना 24.06.2011 को ही एकत्र किया गया (प्रदर्श पृष्ठ 8)। विशेष अधिकारी के ज्ञापन (प्रदर्श पृष्ठ 22) के अनुसार, सभी नमूने 23.08.2011 को एफएसएल भेजे गए थे और डीएनए परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पृष्ठ 25) के अनुसार, जांच के लिए सामग्री 29.08.2011 को प्राप्त हुई थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आरोपी से 24.06.2011 को लिया गया रक्त नमूना डीएनए परीक्षण के लिए हैदराबाद स्थित एफएसएल को 29.08.2011 को प्राप्त हुआ था। हालांकि, अभियोजन पक्ष यह स्पष्ट करने में विफल रहा है कि इतने लंबे समय तक यह नमूना कहां रखा गया था। अन्वेषण अधिकारी ने स्वीकार किया है कि एक्स.पी/20 एसपी, सरगुजा द्वारा डीएनए परीक्षण के लिए लिखा गया था और वह यह नहीं बता सकते कि इसे डीएनए परीक्षण के लिए रायपुर कब भेजा गया था।

29. उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर, हमारा मत है कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी/अपीलकर्ता के विरुद्ध बताए गए किसी भी परिस्थिति को विधि के अनुसार संदेह से परे सिद्ध नहीं किया गया है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण नहीं है कि इससे केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सके कि आरोपी/अपीलकर्ता ही विचाराधीन अपराध का अपराधी है। इसलिए, अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

30. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है और आईपीसी की धारा 363, 366, 376(1) और 302 के तहत आरोपी/अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और दंड पारित करने का निर्णय अपास्त किया जाता है और उसे संदेह का लाभ देते हुए उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह बताया गया कि वह जेल में है, इसलिए यदि किसी अन्य अपराध के संबंध में उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए।

31. बीएनएसएस, 2023 की धारा 481 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष 25,000/- रुपये की राशि का एक व्यक्तिगत बांड और इतनी ही राशि का एक जमानतदार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जो छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा, साथ ही यह वचन भी देना होगा कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर करने या अनुमति प्राप्त करने की स्थिति में, उक्त अपीलकर्ता नोटिस प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। विचारण न्यायालय का अभिलेख और इस निर्णय की प्रति अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित विचारण न्यायालय को तुरंत वापस भेज दी जाए। इस निर्णय की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को भी सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी जाए।



सही/-
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/-
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।